इकाई 30 भारतीय उद्योग का रोज़गार आयाम

इकाई की रूपरेखा

30.0 उद्देश्य
30.1 प्रस्तावना
30.2 कुछ उपयोगी परिभाषाएँ
30.3 भारतीय उद्योग संबंधी आधारभूत आँकड़े (data base)
30.4 भारतीय उद्योग में रोज़गार प्रवृत्तियाँ
30.5 विसमुच्चय दृश्य
30.6 नौकरी हीनता
30.7 इस प्रवृत्ति (पैटर्न) के कारक
30.8 सारांश
30.9 शब्दावली
30.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ
30.11 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

30.0 उद्देश्य

यह इकाई संगठित क्षेत्र में लघु और बृहत् उद्योगों, दोनों में रोज़गार की वृद्धि अथवा ह्रास से संबंधित है। इस इकाई में, हम निम्नलिखित के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे:

- सरकार द्वारा यथा अंगीकृत लघु और बृहत् उद्योगों की परिभाषा क्या है;
- समुच्चय के विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक रोज़गार संबंधी आँकड़ों को कैसे पढ़ा जाए;
- रोज़गार की समय प्रवृत्ति; और
- रोज़गार की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में हम क्या जानते हैं?

30.1 प्रस्तावना

भारतीय उद्योग अपनी विविधता के लिए सुविदित है। इसमें न सिर्फ विशालकाय कारख़ानों से लेकर अत्यन्त ही लघु कारखाने तक सम्मिलित हैं अपितु इनमें कहीं तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है तो कहीं उसी पुरानी प्रौद्योगिकी का। उदाहरण के लिए एक विद्युत संयंत्र में हजारों कर्मकार काम करते हैं जबकि आपके पड़ोस में स्थित मोटर-गैरेज़ में मात्र दो या तीन मेकैनिक ही होते हैं। इसी प्रकार टी वी का विनिर्माण कर रही कंपनी जापान की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही होती है तो टी वी के रिमोट में लगाया जाने वाला बैटरी शायद पुरानी प्रौद्योगिकी से ही बनाया जा रहा हो।

हमारे उद्योग रोज़गार के सृजन में कहाँ तक सफल रहे हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारा अनुभव क्या रहा है? इस इकाई में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ऐसा करते समय हम देखेंगे कि यही विविधता, जिसे बहुधा अर्थशास्त्रियों ने द्वैधता भी कहा है और इसे विकासशील देशों की प्रघटना के रूप में देखा जाता है, कुछ समस्याएँ भी पैदा करता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस द्वैध चरित्र के कारण किसी भी नीति का उद्योग के सभी उप-क्षेत्रों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें से कुछ-लघु और पिछड़ी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर फर्मों- के संबंध में हमारी जानकारी और तथ्यात्मक ज्ञान भी कम है, हालाँकि सैद्धान्तिक स्तर पर हम भलीभाँति समझते हैं कि इन

उप-क्षेत्रों का उनके आधुनिक सहयोगियों के साथ परस्पर स्थिति कैसी होगी। इसलिए, हमारी सर्वोत्तम रणनीति यह होगी कि हम उन्हीं उद्योगों का विश्लेषण करें जिनके संबंध में हमारे पास क्रमबद्ध जानकारी है और फिर दूसरों के सामान्य अनुमानों तथा शोध निष्कर्षों से इस अंतराल को भरा जाए। हम लोग सबसे पहले रोज़गार की समुच्चय प्रवृत्ति पर विचार करेंगे और उसके बाद हम इसकी गहरी छानबीन अधिक विसमुच्चय स्तरों पर करेंगे।

यह विसमुच्चय कई रीतियों से किया जा सकता है। सर्वप्रथम, हम लघु फर्मों को बृहत् फर्मों से पृथक करने के लिए रोज़गार को ले सकते हैं। दूसरा, हम प्रौद्योगिकी के आधार पर भी उद्योगों को दो समूहों, आधुनिक और 'परम्परागत' (विद्युत करघा बनाम हथकरघा, डेस्कटॉप प्रकाशन बनाम परम्परागत मुद्रण इत्यादि) में बाँट सकते हैं। तीसरा, व्यक्ति विशेष की ही भाँति सरकार के स्वामित्व में भी अनेक कारखाने हैं। इसलिए स्वामित्व (निजी बनाम सार्वजनिक) भी वर्गीकरण का एक अन्य आधार हो सकता है।

क्या हमारे पास विसमुच्चय के इन सभी स्तरों के संबंध में आँकड़े हैं? नहीं। हमारे शहरों में जगह-जगह पर स्थापित बड़ी संख्या में लघु इकाइयाँ (उदाहरण के लिए पड़ोस का मोटर गैरेज़) सरकार के पास पंजीकृत हों यह आवश्यक नहीं, हालाँकि उनकी आर्थिक भूमिका उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि टिस्को या रिलायन्स जैसे भीमकाय उद्योगों का। ये कारखाने असंगठित क्षेत्र में आते हैं और इसलिए यह हमारे विश्लेषण के दायरे में नहीं आते हैं।

अगले दो भागों में, हम आपका औद्योगिक रोज़गार से संबंधित कुछ परिभाषाओं और आँकड़ा स्रोतों से परिचय कराएँगे, जहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि हमारे विश्लेषण का आधार मूल रूप से वह क्षेत्र होगा जिसे संगठित विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है।

30.2 कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

किसी कारख़ाना द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों को 'कर्मचारी' कहा जाता है। एक कर्मचारी शारीरिक रूप से श्रम करने वाला, अथवा क्लर्क या एक प्रबन्धक हो सकता है। उन सभी को कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया है। किंतु विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों तथा एसे कर्मचारी जो विनिर्माण प्रक्रिया से अलग हैं के बीच विभेद किया गया है। कर्मचारी जिसे (प्रत्यक्ष अथवा किसी एजेन्सी के माध्यम से) किसी विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य प्रकार के कार्य के लिए नियोजित किया गया है को 'कर्मकार' भी कहते हैं। इस प्रकार क्लर्क को सिर्फ कर्मचारी की सूची में रखा जा सकता है जबकि किसी मेकैनिक को कर्मचारी और कर्मकार दोनों की सूची में रखा जाएगा।

कारख़ाना क्या है? कारख़ाना का अभिप्राय उस परिसर से है जहाँ पिछले बारह महीनों से कम से कम 10 कर्मकार अथवा यदि विनिर्माण प्रक्रिया में विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो कम से कम 20 कर्मकार विनिर्माण प्रक्रिया को सम्पन्न कर रहे हैं। जब कोई कारख़ाना, कारख़ाना अधिनियम 1948 की धारा 2m(i) और 2m(ii) के अंतर्गत, पंजीकृत होता है तो इसे पंजीकृत कारख़ाना कहा जाता है।

एक कारख़ाना वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन कर सकता है। हालाँकि हम सामान्यतया उसे ही उत्पादन सुविधा समझते हैं जिससे भौतिक 'वस्तुओं' (प्लास्टिक, कागज़, कपड़े इत्यादि) का उत्पादन होता है तथा 'सेवाओं' जैसे बैंकिंग, परिवहन अथवा अधिक लौकिक चीजों जैसे बाल काटना और घर की सफाई को उत्पादन कार्य नहीं माना जाता है। किंतु इन दोनों ही क्षेत्रों से जुड़ी फर्में कारख़ाना की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

कारख़ानों को लघु और बृहत् में कैसे वर्गीकृत किया जाता है? समय-समय पर इस परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है क्योंकि विनियम के उद्देश्य और संदर्भों में परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले 1955 में अंगीकृत तथा ***औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम*** में अंतर्निहित मानदंडों में इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कतिपय प्रकार के उद्योगों को पंजीकरण से छूट दी गई है। औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम में 50 से कम कर्मकारों को नियोजित और विद्युत का उपयोग करने तथा 100 से कम कर्मकारों को नियोजित और विद्युत का उपयोग नहीं करने वाले उद्योगों को पंजीकरण से छूट दी गई है। जिस क्षेत्र को छूट दी गई है उसे कारख़ाना इकाइयों के ***लघु क्षेत्र*** के रूप में जाना जाता है। शेष उद्योग, जिनमें 50 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं और विद्युत का उपयोग हो रहा है या 100 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं और विद्युत का उपयोग नहीं हो रहा है, की परिभाषा कारख़ाना इकाइयों के बृहत् क्षेत्र के रूप में की गई है।

तथापि, कर प्रोत्साहन प्रदान करने और वित्तीय विनियमन के लिए, सरकार निवेश आधारित परिभाषा का प्रयोग करती है। इस परिभाषा के अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयाँ, जिनमें पूँजी निवेश 1 करोड़ रु. से अधिक नहीं है, ***लघु क्षेत्र की इकाइयाँ*** मानी जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए पूँजी निवेश का अभिप्राय संयंत्र और मशीनों में निवेश है। भूमि और फैक्टरी भवन को अलग रखा गया है क्योंकि भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूमि के मूल्य में काफी अंतर है। इस प्रकार, सभी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें लघु उद्योगों के मामले यथा विनिर्दिष्ट पूँजी निवेश से अधिक पूँजी निवेश है बृहत् उद्योग हैं।

बोध प्रश्न 1

1) भारतीय उद्योग का अध्ययन करने में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) कुछ विसमुच्चय श्रेणियों का नाम बताएँ जिनमें औद्योगिक क्षेत्र का विभाजन किया जा सकता है।

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'कर्मचारी' और 'कर्मकार' के बीच अंतर बताइए?

.....

.....

.....

.....

.....

4) लघु उद्योग की किसी एक परिभाषा का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

5) पंजीकृत कारख़ाना क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

6) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) कर्मचारी में सिर्फ पुरुष कर्मचारी सम्मिलित हैं, महिला कर्मचारी नहीं। ( )

ख) एक छोटा कारख़ाना सदैव ही अपंजीकृत होता है। ( )

ग) पंजीकृत कारख़ाना लघु अथवा बृहत् हो सकता है। ( )

घ) कारख़ानों में सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का नहीं। ( )

30.3 भारतीय उद्योग संबंधी आधारभूत आँकड़े

शोधकर्त्ता औद्योगिक रोज़गार संबंधी दो महत्त्वपूर्ण आँकड़ा स्रोतों पर निर्भर करते हैं। पहला स्रोत, औद्योगिक उत्पादन और रोज़गार के लिए सुविदित आँकड़ा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ए एस आई) है और दूसरा स्रोत श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण जो प्रतिवर्ष 'लेबर ईयरबुक' में प्रकाशित किया जाता है। इस लेख में हम ए एस आई आँकड़ों का उपयोग करेंगे।

ए एस आई के दायरे में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र आता है जिसमें सभी बृहत् कारखाने और पंजीकृत लघु कारख़ानों का उप समूह सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि 10 या अधिक कर्मकारों वाले सभी कारख़ानों (विद्युत का उपयोग करने वाले) द्वारा पंजीकरण कराने की अपेक्षा की जाती है और इन्हें ए एस आई द्वारा अपने सर्वेक्षण में सम्मिलित किया जा सकता है। किंतु इस तरह के अनेक कारख़ाने, रोज़गार अथवा निवेश के मानदंडों के आधार पर लघु उद्योग की परिभाषा के अनुरूप हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए, ए एस आई आँकड़ों को मिसाल के तौर पर कारख़ाना क्षेत्र का आँकड़ा कहा जाता है।

ए एस आई पद्धति के अनुसार, पूँजी, रोज़गार और उत्पादन संबंधी विस्तृत आँकड़ा प्रतिष्ठान स्तर पर एकत्रित किया जाता है और उसके बाद समुच्चयन के विभिन्न स्तरों पर उनका सार-संक्षेप तैयार किया जाता है। जैसा कि खंड 1 की इकाई 3 में स्पष्ट किया गया है समुच्चयन का उच्चतम स्तर आमतौर पर सभी उद्योगों का समुच्चय है। समुच्च्यन का दूसरा स्तर (और जिसका अधिकांशतया उपयोग किया जाता है) 'दो अंक' वाला स्तर कहा जाता है। 'दो अंक' विसमुच्चयन का पहला स्तर है और इसका विसमुच्चयन पुन: तीन या चार अंक स्तरों में प्रत्येक अलग-अलग उद्योगों के लिए किया जा सकता है।

बोध प्रश्न 2

1) औद्योगिक रोज़गार संबंधी आँकड़ों के मुख्य स्रोत क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

2) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) ए एस आई में कारख़ाना क्षेत्र सम्मिलित है। ( )

ख) ए एस आई रोज़गार संबंधी जानकारी एकत्र नहीं करता है। ( )

ग) 'दो अंक' वाले वर्गीकरण में सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित है न कि सेवाएँ। ( )

30.4 भारतीय उद्योग संबंधी रोज़गार प्रवृत्तियाँ

औद्योगिकरण के नियोजित प्रयासों से भारत आधुनिक उद्योगों के विशाल संजाल (नेटवर्क) का सृजन कर रहा है जिसमें बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित तथा तैयार वस्तुओं दोनों का उत्पादन किया जा रहा है। तथापि, प्रौद्योगिकीय क्षमता में यह उपलब्धि रोज़गार के स्वरूप में संरचनात्मक परिवर्तन के अनुरूप नहीं हुआ है। हमारी अधिकांश जनसंख्या (60 प्रतिशत से अधिक) अभी भी कृषि क्षेत्र में ही नियोजित है, हमारे उद्योगों का रोज़गार में कुल हिस्सा 15 प्रतिशत के लगभग है और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र से आता है। इसे अच्छा रिकार्ड नहीं कहा जा सकता है, विशेष कर इस तथ्य के मद्देनजर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र को सरकार से भारी संरक्षण मिला है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, पंजीकृत विनिर्माण इकाइयाँ कुल श्रम बल के 20 प्रतिशत को रोज़गार देता है किंतु योजित मूल्य (निर्गत का माप) में इसका हिस्सा 66 प्रतिशत है, जबकि शेष अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रों से आता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र जिसे सरकार के समर्थन और नियोजन का सर्वाधिक लाभ मिला है, सापेक्षिक रूप से अधिक पूँजी-सघन है तथा यह हमारे विशाल श्रम-बल को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मुहैया कराने में असफल रहा है। तथापि, जैसा कि हमारे योजना निर्माताओं ने सोचा था, इस क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, और परोक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों में रोज़गार का सृजन किया है। तथापि, यह जाँच का विषय हो सकता है।

तालिका 30.1 : रोज़गार प्रवृत्ति

वर्ष	कर्मकार (लाख में)	सभी कर्मचारी (लाख में)	कुल कर्मचारियों में कर्मकारों का प्रतिशत
1960-61	-	36.43	-
1965-66	-	46.96	-
1970-71	42.30	52.15	81
1975-76	49.96	63.80	78
1980-81	60.46	77.14	78
1985-86	58.19	74.71	77
1990-91	63.07	81.62	77
1995-96	76.32	100.44	76

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

अब हम रोज़गार में दीर्घकालीन प्रवृत्ति पर दृष्टिपात करते हैं, जो तालिका 30.1 में दिखाया गया है। वर्ष 1960-61 में औद्योगिक रोज़गार लगभग 36 लाख (3.6 मिलियन) था, और 38 वर्षों के बाद 1998 में यह बढ़कर 10 मिलियन (1 करोड़) हो गया अर्थात् मात्र तीन गुना वृद्धि हुई है। यद्यपि कि इस तालिका में हमने सिर्फ संक्षिप्त आँकड़ा (पाँच वर्षों के अंतराल पर) ही लिया है, विस्तृत वार्षिक आँकड़ों से भी न्यूनाधिक यही परिलक्षित होता है कि वृद्धि की रफ्तार अत्यन्त ही धीमी रही है। कभी-कभी अपवाद स्वरूप उछाल को छोड़कर धीमी गति से रोज़गार में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जिसमें अस्सी के दशक के दौरान भारी कमी आई थी। जैसा कि इस संक्षिप्त आँकड़े में भी देखा जा सकता है, वर्ष 1985-86 के कर्मकारों और कर्मचारियों दोनों के आँकड़े 1980-81 के तदनुरूपी आँकड़ों की तुलना में कम है। हम पहले ही देख चुके हैं कि 'कर्मचारी' में सभी पदनामों के कर्मकार सम्मिलित हैं (अर्थात् शारीरिक श्रम करने वाले और कार्यालयी कार्य करने वाले दोनों), जबकि 'कर्मकार' का अभिप्राय विनिर्माण प्रक्रिया में (मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करने वाले) सम्मिलित कर्मकारों से है। कर्मचारियों की दोनों ही श्रेणियों में वृद्धि की गति धीमी रही है। 'कर्मकार' कहलाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत, हालाँकि इसमें भी ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति दिखाई जाती है, विगत तीस वर्षों तक लगभग 77 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, जिससे यह पता चलता है कि फर्मों के श्रम बल संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

तालिका 30.2 : रोज़गार की औसत वृद्धि दर (प्रतिशत)

	उद्योग का वास्तविक योजित मूल्य	उद्योग में नियोजित पूँजी का वास्तविक मूल्य	औद्योगिक क्षेत्र रोज़गार	कारख़ानों की संख्या	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
1960-70	6.86	8.51	3.68	-	3.82
1970-80	4.59	2.90	4.00	-	3.15
1980-90	8.37	6.38	0.60	0.6	5.67
1990-97	9.30	-	2.58	3.05	4.6*
1960-90	6.25	5.71	2.69	-	4.15

*1990-95 के लिए

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

तालिका 30.2 में हमने कुछ महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी प्रस्तुत किया जो कुछ महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचकों के संबंध में रोज़गार कार्य-निष्पादन की व्याख्या करते हैं। इसके माध्यम से कई बातें आसानी से बताई जा सकती हैं। पहला, पिछले चालीस वर्षों में इस क्षेत्र में रोज़गार वृद्धि दर नियोजित पूँजी की वृद्धि दर उत्पादित निर्गत की वृद्धि दर और सकल घरेलू उत्पाद में समग्र वृद्धि दर की अपेक्षा कम रही है। दूसरा, यह क्षेत्र मुख्य रूप से पूँजी-सघन क्षेत्र रहा और श्रम के उपयोग से अधिक पूँजी के उपयोग में वृद्धि हुई। तीसरा, स्वयं औद्योगिक क्षेत्र गतिहीन नहीं है। वर्ष 1960 और 1990 के बीच इसके योजित मूल्य (अथवा निर्गत) में, 6.25 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। इस तथ्य के मद्देनजर कि औद्योगिक क्षेत्र ही सामान्यतया प्रमुख क्षेत्र है जो व्यापार-चक्र (जैसे मंदी अथवा तेजी) से प्रभावित होता है, यह वृद्धि दर तुच्छ नहीं है। चौथा, जब हम विभिन्न दशकों में रोज़गार वृद्धि का विश्लेषण करते हैं तो हम U-आकार का पैटर्न बनता देखते हैं। वर्ष 1960-80 के बीच अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर से शुरू होने के बाद 1980 और 1990 के बीच इसमें गिरावट आई और उसके बाद 1990 के दशक में पुन: वृद्धि दर ऊपर चढ़ने लगी जो स्थिति के पलट जाने का द्योतक है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसी पैटर्न के कारण 1980 के दशक को 'नौकरी विहीन वृद्धि का दशक' कहा है।

यह प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण क्यों है? इसका एक कारण यह है कि यह न्यूनाधिक हमारे नीतिगत परिवर्तनों के प्रवृत्ति (पैटर्न) का अनुसरण करता है। जहाँ साठ के दशक में नियंत्रण, औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली और विनियमन की शुरुआत हुई थी, सत्तर के दशक में ये सर्वव्यापी हो चुके थे। किंतु अस्सी के दशक के मध्य से आंशिक तौर पर विनियमन में ढील देना शुरू हुआ और उसके बाद अंत: 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपनाया गया। इसलिए, यह जाँच-पड़ताल करना अत्यन्त ही स्वभाविक है कि क्या उद्योग के नियोजन कार्यनिष्पादन का सरकार की आर्थिक नीतियों से निकट संबंध था। इस प्रश्न पर हम बाद में चर्चा करेंगे।

रोज़गार की प्रवृत्तियों पर अपनी चर्चा जारी रखते हुए यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि नब्बे के दशक में रोज़गार की औसत वृद्धि दर में बढोत्तरी हुई जो कि अत्यन्त ही सकारात्मक रुख है किंतु बीच-बीच में उतार-चढ़ाव चिन्ता की बात है। विगत दशक में कम से कम तीन वर्षों में प्राय: शून्य वृद्धि दर्ज किया गया, और एक वर्ष (1996-97) में रोज़गार में समग्र गिरावट आई। इससे अनेक अर्थशास्त्रियों के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि उद्योग में सुधार का रुख टिकाऊ होगा अथवा नहीं। इसके अलावा यह भी देखा गया कि अपंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में, जहाँ लगभग 80 प्रतिशत रोज़गार का सृजन होता है, कुछ शोध निष्कर्षों के अनुसार, नौकरियों की संख्या में समग्र गिरावट के संकेत हैं। किंतु ये परिणाम प्रामाणिक नहीं हैं।

बोध प्रश्न 3

1) विगत चालीस वर्षों में रोज़गार प्रवृत्ति की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या रोज़गार वृद्धि निर्गत के समरूप हुई।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'नौकरीविहीन वृद्धि' से हमारा अभिप्राय क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) वर्ष 1980 से औद्योगिक रोज़गार में गिरावट आ रही है। ( )

ख) वर्ष 1960 से 1980 तक निर्गत और रोज़गार दोनों में वृद्धि हुई। ( )

ग) नब्बे के दशक में, रोज़गार वृद्धि सकारात्मक रही है। ( )

घ) अस्सी के दशक में, औद्योगिक निर्गत में बहुत वृद्धि नहीं हुई। ( )

30.5 विसमुच्चय दृश्य

हमने अब तक औद्योगिक रोज़गार का बिल्कुल समुच्च्य चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम कुछ विसमुच्च्य श्रेणियों पर चर्चा करेंगे।

विशेष उद्योग: पहले हम उन उद्योगों पर दृष्टि डालते हैं जिनमें रोज़गार का सृजन अधिक होता है। तालिका 30.3 से पता चलता है कि 26 औद्योगिक समूहों में से मुख्यत: 8 ही अधिसंख्य कर्मकारों को रोज़गार देने का उत्तरदायित्व वहन कर रहे हैं। रोज़गार के मामले में कुल मिलाकर उनका हिस्सा आधे से भी ज्यादा है और निर्गत में भी उनका हिस्सा लगभग आधे के बराबर ही है।

तालिका 30.3: रोज़गार में हिस्सा

उद्योग कूट	विवरण	1980-81	1990-91	1995-96
20-21	खाद्य और खाद्य उत्पाद	16.71	13.41	11.94
23	सूती वस्त्र	13.88	7.62	8.00
33	मूलभूत धातु और मिश्रधातु (एलॉय)	7.49	10.37	6.84
35-36	परिवहन से भिन्न मशीनें	9.20	5.82	9.09
37	परिवहन उपकरण और कल पुर्जे	6.28	10.67	5.75
40	विद्युत	9.47	10.67	10.65
	योग	**63.03**	**57.99**	**52.27**
इन आठ उद्योगों का कुल योजित मूल्य में हिस्सा		54.00	43.65	48.90

सार्वजनिक क्षेत्र

पचास के दशक के मध्य दूसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने के समय यह बिलकुल स्पष्ट था कि सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अधिक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्प थी। किंतु, मूलत: इस भूमिका को आधारभूत संरचना (रेलवे, सड़क इत्यादि) और कुछ बुनियादी उद्योगों (जैसे इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद) के निर्माण तक ही सीमित रहना था। परंतु, साठ के दशक के उत्तरार्द्ध से अन्य क्षेत्रों में भी इस भूमिका का विस्तार हुआ। जहाँ अनेक नियंत्रणकारी उपाय जैसे लाइसेंस पद्धति, अत्यधिक टैरिफ और आयात पर प्रतिबन्धों ने निजी उद्योग और व्यवसाय की भूमिका को कम किया, उपक्रमों पर सीधे स्वामित्व से सरकारी विनियमन और प्रबन्धन का स्वरूप और अधिक प्रभावी हुआ। यह सरकार की हस्तक्षेपवादी नीति के तहत निर्धारित विभिन्न सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के भी अनुरूप था। साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में और सत्तर के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या में भारी वृद्धि (1966 में 77 से 1980 में 180, देखिए

तालिका 30.4) हुई। बाद के दशकों में वृद्धि की गति धीमी हुई और अंत: 1990 के दशक से सरकार ने 'राष्ट्रीयकरण' की अपनी नीति में परिवर्तन किया तथा 'निजीकरण' की नीति अपना ली। इसका बिल्कुल सीधा अर्थ यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या में गिरावट आ सकती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के कई विद्यमान उपक्रमों को निजी क्षेत्र के बोली लगाने वालों के हाथ बेच दिया जाएगा। चूँकि सरकारी स्वामित्व का एक मुख्य उद्देश्य रोज़गार का सृजन था, नीति में यह परिवर्तन कुछ चिन्ता पैदा करता है। राष्ट्रीयकरण के आरम्भिक वर्षों में इस क्षेत्र में रोज़गार की तेजी से वृद्धि हुई किंतु अस्सी के दशक के बाद, आवश्यकता से अधिक श्रमिकों और उससे संभावित हानि की आशंका से, सरकार ने विभिन्न तरीकों के माध्यम से श्रमबल को युक्तिसंगत बनाने का कार्य शुरू कर दिया।

तालिका 30.4 : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रोज़गार

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारी (हजार में)	कर्मचारी (लाख में)
1961	47	-	-
1966	73	-	-
1974	122	-	-
1980	168	10.95	18.39
1985	215	9.82	21.11
1990	244	9.09	22.17
1995	245	8.37	20.50

स्रोत : सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण

चित्र 30.1 : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रोज़गार (लाख में)

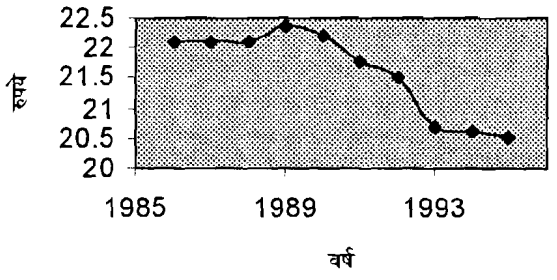

इसमें रिक्त पदों को नहीं भरना, अनेक पदों को समाप्त करना, कर्मकारों को निर्धारित समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने इत्यादि के लिए प्रेरित करना सम्मिलित है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में रोज़गार की कुल संख्या में ह्रास हुआ। इस चरण को चित्र 30.1 में ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है जहाँ हमने विस्तृत वार्षिक आँकड़ा प्रस्तुत किया है। रोज़गार में गिरावट के कारण, किंतु इकाइयों की संख्या यथावत् रहने से वर्ष 1980 में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उपक्रम 11 हज़ार रोज़गार (अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का औसत आकार) में गिरावट आई तथा यह 1995 में 8 हज़ार

से कुछ अधिक रह गया। इतना होने पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के एक औसत उपक्रम में रोज़गार अभी भी अर्थव्यवस्था की एक औसत औद्योगिक इकाई की तुलना में बहुत ज्यादा (लगभग 100 गुणा) है। इसका कारण यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मुख्य रूप से बृहत्-पूँजी-सघन बुनियादी वस्तु क्षेत्र में कार्यरत हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र: ऐसा प्रतीत होता है कि लघु उद्योगों का कार्य निष्पादन फैक्टरी सेक्टर की तुलना में अधिक अच्छा रहा है। भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है जिन्होंने उत्पाद आरक्षण, उत्पाद शुल्क में छूट, राज सहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) ऋण इत्यादि के रूप में विशेष लघु उद्योगोन्मुखी नीति का लम्बे समय तक अनुसरण किया है। हालाँकि, विगत दस वर्षों में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की संख्या में भारी कमी आई है फिर भी मोटे तौर पर संवर्द्धनात्मक नीति अभी भी जारी है। किंतु शोधकर्त्ताओं की दृष्टि में लघु उद्योगों के लिए कोई भी क्रमबद्ध और विश्वसनीय आधारभूत आँकड़ा नहीं है। उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले आँकड़े के साथ एक गंभीर समस्या यह है कि लघु उद्योग की परिभाषा में, जो पूँजी के अंकित मूल्य पर आधारित है, बार-बार परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण, शोधकर्त्ता गैर सरकारी सर्वेक्षणों पर अथवा अन्य स्रोतों जैसे जनगणना या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आँकड़ा पर निर्भर करते रहे हैं।

तथापि, यहाँ हम उद्योग मंत्रालय के आँकड़ों का उपयोग करेंगे तथा जनगणना से कुछ अनुमानों का भी संदर्भ लेंगे। आँकड़ों की अनुरूपता की समस्या के साथ-साथ अर्थशास्त्री सामान्यतया इस बात से भी सहमत हैं कि पिछले दो तीन दशकों में शुरू से अंत तक लघु उद्योगों में गतिशीलता और वृद्धि दिखाई पड़ती है। जैसा कि तालिका 30.5 में दर्शाया गया है, इस क्षेत्र में 1995 और 1998 के बीच रोज़गार में तीन गुणा वृद्धि हुई है और यह 1.71 करोड़ तक पहुँच गया है जो कि समस्त फैक्टरी सेक्टर रोज़गार से काफी अधिक है। इतना ही नहीं, रोज़गार में तब भी समरूप वृद्धि हुई जब अस्सी के दशक में बृहत् फैक्टरियों में रोज़गार में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई थी। तथापि, रोज़गार की वृद्धि दर (देखिए तालिका 30.6) हालाँकि अभी भी महत्त्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है, सत्तर के दशक में प्रभावशाली 8.7 प्रतिशत से गिर कर नब्बे के दशक में 4 प्रतिशत के साधारण स्तर तक आ गया है और इसमें निर्गत वृद्धि दरों की अपेक्षा कम वृद्धि के रूप में देखा गया जैसा कि बृहत् फैक्टरियों के मामले में है। समय बीतने के साथ एक छोटी फैक्टरी का औसत आकार (कर्मचारी के मामले में) और छोटा होता जा रहा है।

तालिका 30.5 : लघु उद्योगों में रोज़गार

वर्ष	रोज़गार (लाख)	प्रति कारख़ाना कर्मचारी
1975-76	45.9	8.41
1980-81	71	8.12
1985-86	96	7.10
1990-91	125.3	6.43
1994-95	146.6	5.7
1998-99	171.58	5.49

स्रोत : उद्योग मंत्रालय प्रतिवेदन

तालिका 30.6 : लघु उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर

वर्ष	निर्गत वृद्धि दर	रोज़गार वृद्धि दर
1973-80	-	8.7
1980-90	10.73	5.84
1990-95	6.20	4.0
1990-95	9.4	4.0

स्रोत: उद्योग मंत्रालय प्रतिवेदन

छोटे फैक्टरियों में रोज़गार का वैकल्पिक माप गैर पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से छोटे फैक्टरी (किंतु निश्चित तौर पर पंजीकृत छोटे फैक्टरियों को छोड़ देते हैं, इसमें से कुछ ए एस आई आँकड़ों द्वारा कवर किए जा सकते हैं) सम्मिलित हैं, के रोज़गार अनुमानों में पाया जा सकता है। जनगणना आँकड़ों से निकाले गए ऐसे अनुमानों से पता चलता है कि 1981 में इस क्षेत्र में रोज़गार 13.58 मिलियन (1.35 करोड़) था जो 1991 में बढ़ कर 15.64 मिलियन हो गया और आरम्भिक रिपोर्टों के अनुसार 2001 में 28.20 मिलियन तक पहुँच गया है - अर्थात् विगत दस वर्षों में इस क्षेत्र में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

बोध प्रश्न 4

1) कुछ उद्योगों का नाम बताएँ जिनमें सत्त् रूप से अधिक रोज़गार का सृजन हुआ है।

.....

.....

.....

.....

.....

2) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पी एस यू) में रोज़गार की प्रवृत्ति क्या रही है, चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) रोज़गार में, कुल स्तरों और वृद्धि दरों दोनों के संदर्भ में, लघु उद्योगों के योगदान पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

4) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) फैक्टरी क्षेत्र की अपेक्षा लघु क्षेत्र में रोज़गार की वृद्धि दर कम रही है। ( )

ख) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अभी भी रोज़गार में वृद्धि हो रही है। ( )

ग) रोज़गार में खाद्य और खाद्य उत्पाद उद्योगों का हिस्सा 10 प्रतिशत से कम है। ( )

घ) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या में अधिकांश वृद्धि 1960 और 1980 के बीच हुई है। ( )

ड.) वर्ष 1980 तक, सरकार की आर्थिक नीति मुक्त-बाज़ारोन्मुखी नहीं थी। ( )

30.6 बेरोज़गारी और नौकरी हीनता

बेरोज़गारी और नौकरीहीनता का अध्ययन रोज़गार के स्वरूप में कैसी वृद्धि हो रही है उस पर विचार करने का एक अन्य तरीका है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नौकरीहीनता और बेरोज़गारी में थोड़ा अंतर है। बेरोज़गारी में जहाँ सभी प्रकार की बेरोज़गारी शामिल है, नौकरीहीनता का अभिप्राय नौकरी की समाप्ति है। इसलिए बेरोज़गारी में नौकरीहीनता सम्मिलित है किंतु नौकरीहीनता में बेरोज़गारी सम्मिलित नहीं है। नौकरीहीनता की स्थिति तब आती है जब कोई क्षेत्र अचानक अपना बाज़ार खो बैठता है और आयात, अथवा अर्थव्यवस्था में अन्यत्र प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के विकास या प्रतिकूल नीतिगत परिवर्तनों के कारण कम प्रतिस्पर्धी रह जाता है।

भारतीय संदर्भ में, नौकरीहीनता के संबंध में स्पष्ट आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, फर्मों की स्थापना और उनके बंद होने के संबंध में ए एस आई आँकड़ों का उपयोग करके इसे मापा जा सकता है। राय (2001) ने इस तरह का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। उनके अध्ययन के अनुसार, इकाइयों के बंद होने से 1980 और 1990 के बीच 2.14 मिलियन नौकरियाँ छूट गई। इस तथ्य के मद्देनजर कि यह दशक नौकरीविहीन वृद्धि का था, यह आश्चर्यजनक नहीं है। नब्बे के दशक में इस स्थिति में सुधार हुआ है। विशेषकर, 1990 और 1997 के बीच जब निर्गत वृद्धि दर में और वृद्धि हुई और रोज़गार में भी वृद्धि होना शुरू हुआ, सिर्फ 0.45 मिलियन नौकरियाँ छूटी। इसके विपरीत, मंदी प्रभावित 1997-98 में अकेले नौकरी छूटने की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और यह 0.29 मिलियन तक पहुँच गया। यह वर्ष 1990 में 1.4 मिलियन नौकरियाँ छूटने की अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुरूप है। इन आँकड़ों को देखकर, और विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में नौकरी छूटने की घटना में हुई आकस्मिक वृद्धि के कारण नौकरीहीनता की प्रवृत्ति पर चिन्ता और बढ़ गई है।

नौकरीहीनता, चूँकि दिवालियापन और उत्पादन इकाई के बंद होने से संबंधित है, संबंधित माप रुग्ण (अर्थात् वित्तीय रूप से संकट में और संभवतया बंद) इकाइयों में कार्यरत कर्मकारों की संख्या है। इन फर्मों में नौकरियाँ (अथवा रोज़गार) या तो छूट चुकी हैं अथवा भविष्य में छूट जाने की संभावना है, और उन्हें मोटे तौर पर 'संकट में नौकरी' कहा जा सकता है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) के अनुसार, सन् 2000 में 'रुग्ण' इकाई के रूप में पंजीकृत इकाइयों की संख्या बढ़कर 3296 हो गई जिसमें 1.88 मिलियन कर्मकार कार्यरत थे, जो कि संगठित उद्योग में श्रमबल का 20 प्रतिशत है। इसलिए औद्योगिक नौकरियों का 20 प्रतिशत वास्तव में संकट में था इससे पता चलता है कि भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धापूर्ण नए वातावरण में समायोजन करने में कठिनाई हो रही है तथा कई पुराने फर्म वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। तथापि, यह आर्थिक सुधारों के संदर्भ में अस्वाभाविक नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र से बाहर, बेरोज़गारी का अर्थव्यवस्था-व्यापी माप राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा एकत्रित पारिवारिक सर्वेक्षण आँकड़ा और राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित रोज़गार कार्यालय आँकड़ा में से प्राप्त किया जा सकता है। एन एस एस ओ पाँच वर्षों के अंतराल में परिवारों के रोज़गार विवरणों के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण करता है। वर्ष 1987-88 और 1993-94 के उनके आँकड़ों के अनुसार इस समयावधि में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तथा महिलाओं और पुरुषों दोनों में तथा न्यूनाधिक सभी शैक्षणिक स्तरों में बेरोज़गारी में गिरावट आई है। यह औद्योगिक रोज़गार के दृश्य के अनुरूप ही प्रतीत होता है (अर्थात् नब्बे के दशक में विकास) जैसा कि हमने पहले देखा है। लगभग 30 प्रतिशत वयस्क पुरुषों (15 वर्ष की आयु से अधिक के) बेरोज़गार होने की बात कही गई है।

रोज़गार कार्यालयों की रिक्ति रजिस्टर में नौकरी खोजने वालों का नाम दर्ज किया जाता है। इस स्रोत के अनुसार सन् 1970 में बेरोज़गारों की कुल संख्या 4.06 मिलियन से बढ़कर 1987 में 30.24 मिलियन हो गई है जो कि लगभग सात गुणा वृद्धि है। इस समयावधि में बेराजगारी की वृद्धि दर 1980 के दशक (9.85 प्रतिशत) की तुलना में सत्तर के दशक में अधिक तीव्र (13.86 प्रतिशत) रही। वर्ष 1994 में नौकरी खोजने वालों की संख्या बढ़ कर 45 मिलियन हो गयी।

बोध प्रश्न 5

1) 'बेरोज़गारी' और 'नौकरी हीनता' के बीच विभेद कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) नौकरीहीनता की समस्या सामान्यतया कब पैदा होती है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) एन एस एस ओ आँकड़ा के अनुसार अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी बढ़ रही है। ( )

ख) नौकरी हीनता का माप करना कठिन है। ( )

ग) रुग्ण उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों पर नौकरी छूटने का खतरा नहीं होता है। ( )

30.7 इस प्रवृत्ति (पैटर्न) के कारक

अब हम एक अधिक रोचक प्रश्न लेते हैं : औद्योगिक रोज़गार की यह अत्यन्त ही विचित्र (U-आकृति) प्रवृत्ति किन कारकों के कारण होती है? इस प्रश्न को हम तीन अलग-अलग समयावधियों के लिए कर सकते हैं : (1) वर्ष 1980 की प्रवृत्ति (2) अस्सी के दशक के दौरान प्रवृत्ति और (3) नब्बे के दशक में प्रवृत्ति।

पहले चरण (वर्ष 1960 से 1980 तक) में रोज़गार की वृद्धि दर बढ़ रही थी (हालाँकि यह वृद्धि दर मामूली थी), जबकि सकल घरेलू उत्पाद अथवा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही थी। उस समय आयात प्रतिस्थापन्न उपायों पर बल दिया जा रहा था तथा पूँजी विनियतन में बाज़ार की भूमिका पर काफी नियंत्रण लगाया गया था। साथ ही साथ, सरकार ने अधिक से अधिक आर्थिक कार्यकलापों को अपने सीधे स्वामित्व और नियंत्रण में ले लिया जिसका स्पष्ट उद्देश्य रोज़गार के सृजन पर बल था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोज़गार में तेजी से वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र में पूँजी का स्थानापन्न श्रम था क्योंकि सरकारी नियंत्रण के कारण पूँजी दुर्लभ होती जा रही थी इसलिए, मुख्य रूप से सरकारी नीति के परिणामस्वरूप उत्पादन वृद्धि की अपेक्षा रोज़गार में कहीं अधिक वृद्धि हुई।

लेकिन उसके बाद दूसरा चरण आया, जिसमें यह प्रवृत्ति बिल्कुल पलट गई। रोज़गार में वृद्धि लगभग स्थिर हो गई और अचानक उत्पादन वृद्धि बढ़ गई। यह अत्यन्त ही भ्रामक स्थिति थी, क्योंकि आप इन दोनों के बीच सकारात्मक संबंध की अपेक्षा कर सकते हैं। यह वृद्धि नौकरी हीन क्यों थी? अर्थशास्त्री इसके लिए दो युक्ति संगत उत्तर देते हैं : (1) अत्यधिक क्षमता, (2) श्रम बाज़ार की अनम्यता। अस्सी के दशक तक, विभिन्न महत्त्वपूर्ण आदानों जैसे सीमेन्ट, इस्पात, रसायन और यहाँ तक कि वित्तीय पूँजी का वितरण सीधे सरकार के नियंत्रण में था। यहाँ तक कि नए संयंत्र की स्थापना, अथवा क्षमता के विस्तार के लिए भी सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए इस वातावरण में, फर्मों ने सरकार से अनुमति प्राप्त करने की परेशानियों से बचने के लिए अत्यधिक क्षमता के निर्माण का प्रयास किया। अतएव बाद में, जब आर्थिक तेज़ी आई तो उन्होंने अपनी पूर्व निर्मित बेकार पड़ी हुई क्षमता का ही दोहन किया। इस रणनीति ने रोज़गार वृद्धि की गुंजाइश को समाप्त कर दिया। क्षमता आधिक्य की दलील का निचोड़ यही है।

अनम्य श्रम बाज़ार तर्क में भी अनुरूप दृष्टिकोण पाया जाता है। वर्ष 1970 से शुरू होकर ट्रेड यूनियन धीरे-धीरे अपने सदस्यों की संख्या और नियोजकों के साथ अपने मोल-तोल की बढ़ी हुई क्षमता, दोनों रूपों में अधिक सुदृढ़ हो गए थे। इसके साथ ही सरकार ने भी कतिपय विधान बनाए जिससे नौकरी संबंधी सुरक्षा को पक्का किया गया। इस कानून ने काम बंदी, छंटनी और निजी क्षेत्रों (जिसमें 100 कर्मकार या अधिक नियोजित हैं) की बंदी पर प्रतिबंध का रूप ले लिया जो सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन पर्यन्त नौकरी-सुरक्षा के सदृश था। इससे संभवतया कर्मकारों की मोल-तोल की शक्ति में वृद्धि होने लगी और इसके परिणामस्वरूप मज़दूरी में वृद्धि हुई। इसने प्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के रोज़गार को प्रभावित किया तथा विशेषकर बड़ी फर्मों को अपने श्रम बल के प्रबन्धन में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने को प्रेरित किया। अधोमुखी अनम्यता से विवश होकर उन्होंने स्थायी संवर्ग में कर्मकारों को रखना कम कर दिया और ज़हाँ कहीं भी संभव है इसके स्थान पर ठेका मजदूर रखना शुरू किया अथवा बाहर से कर्मकारों को बुलाना शुरू किया। इन सबका संचयी प्रभाव यह हुआ कि पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के रोज़गार में जड़ता आ गई।

अस्सी के दशक में, जब सरकार श्रम कानूनों को और अधिक कठोर बना रही थी, इसने उत्पाद बाज़ार के प्रति बिल्कुल ही अलग नीति अपनाई। अनेक क्षेत्रों में इसने नियंत्रण हटा लिया (जैसे सीमेन्ट और इस्पात के मूल्य निर्धारण पर से नियंत्रण हटाना), विदेशी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दी गई और कतिपय उद्योगों का आधुनिकीकरण भी शुरू किया गया। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में नियमों में क्रमश: ढील के संकेत, अधिक खुलापन और निवेश अनुकूलता आदि सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुके थे और निजी क्षेत्र ने परिवर्तन के इस नए दौर में अत्यन्त ही सकारात्मक प्रतिक्रिया की। सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन दोनों में भारी वृद्धि हुई और अंत: पिछले दशक की वृद्धि की 'हिन्दू दर' जो मात्र 3 से 4 प्रतिशत थी, की सीमा को पार करने में सफल रहा। विशेषकर, निर्यात बढ़ना शुरू हुआ।

उसके बाद नब्बे का दशक आया जब 1991 में अभूतपूर्व भुगतान संतुलन के संकट ने सरकार को पूर्ण रूप से आर्थिक सुधार करने के लिए बाध्य कर दिया, इसमें से अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण शर्तें थीं। हालाँकि अपना देश पहले से ही सुधार के पथ पर बढ़ रहा था किंतु 1991 के संकट ने अकस्मात ही सुधार की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। घरेलू प्रतिस्पर्धा पर प्राय: सभी प्रत्यक्ष नियंत्रण (लाइसेन्स प्रणाली, प्रवेश की अनुमति के रूप में) जल्दी-जल्दी हटा लिए गए, निजी क्षेत्र का स्वागत पहले से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाने के लिए किया गया और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विस्तारवादी स्वरूप पर जानबूझ कर नियंत्रण लगाया गया। इसके अलावा, देश के विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण करने से विदेश व्यापार पर से बहुत सारी पाबंदियाँ हटा ली गईं। बाज़ारोन्मुखी सुधार प्रक्रिया के अंग के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्बाध आयातों की अनुमति दी गई।

सुधारों के इस परिदृश्य में, 1990 के दशक में रोज़गार संबंधी प्रवृत्तियों को नई नीतियों की कसौटी पर परखा जाना स्वाभाविक है। अर्थशास्त्रियों ने दो प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। एक तर्क यह है कि रोज़गार के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप में ही सुधारों के सकारात्मक परिणाम के प्रमाण हैं। निर्यात का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सकारात्मक प्रभाव त्तकाल महसूस किया गया। नब्बे के दशक के आरम्भ में, निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हुई और इस निर्यात में लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों के श्रम-प्रधान वस्तुओं का बड़ा हिस्सा था। इसने निश्चित तौर से रोज़गार वृद्धि में योगदान किया। किंतु नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में इस गति को नहीं बनाए रखा जा सका। यह चर्चा का एक अलग विषय है जिसका कारण निर्यात में कमी और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट बताया जा सकता है।

दूसरी विचारधारा जो अधिक सतर्क है तथा कभी-कभी सुधार को शंका की दृष्टि से भी देखता है, इस सकारात्मक प्रभाव के चरण के स्थायित्व के संबंध में सचेत भी करता है। इस तथ्य के मद्देनजर कि 1997 के बाद से रोज़गार में वृद्धि दर धीमी हुई है और मंदी की स्थिति बन रही है, इस विचारधारा के अनुसार सुधार की प्रक्रिया से कर्मकारों की दुर्दशा हुई है तथा भविष्य में सस्ती वस्तुओं के खुले आयात से उनकी दशा और खराब होगी।

बोध प्रश्न 6

1) अस्सी के दशक तक हमारी आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) अर्थशास्त्रियों का अस्सी के दशक के नौकरीहीन विकास के संबंध में क्या कहना है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) वर्ष 1991 के बाद किस प्रकार के नीतिगत परिवर्तन हुए?

.....

.....

.....

.....

.....

4) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) आर्थिक सुधार का अभिप्राय अधिक सरकारी नियंत्रण है। ( )

ख) वर्ष 1991 के सुधारों के बाद से निर्यात में गिरावट आई है। ( )

ग) सुधारों के साथ रोज़गार में वृद्धि हुई है। ( )

30.8 सारांश

संक्षेप में, आर्थिक सुधारों से उच्च उत्पादन वृद्धि के रूप में निश्चित तौर पर लाभ हुआ है किंतु इसके साथ ही उद्योग और रोज़गार के पुनर्गठन तथा परिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। यह प्रक्रिया लम्बे समय तक चल सकती है तथा यह विशेषकर मजदूर वर्ग के लिए कुछ कष्टप्रद भी हो सकती है। तथापि, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम सुधार का रास्ता छोड़ दें क्योंकि मजदूरों का बेरोज़गार होना इस पूरी सुधार प्रक्रिया का गौण प्रभाव है, और इसके साथ अनुपूरक नीतियों के माध्यम से अलग से निबटा जा सकता है। यहाँ यह भी अनिवार्य हो जाता है कि इस तरह की नीतियाँ बनाते समय जबरी छुट्टी कर दिए गए श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

30.9 शब्दावली

आर्थिक द्वैधता : एक अर्थव्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में द्विभक्तीकरण जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक कार्यकलापों (जैसे उत्पादन) के संचालन की दो समानान्तर व्यवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं और अलग-अलग नीतिगत पक्षों का विकास होता है।

सकल घरेलू उत्पाद का वास्तविक मूल्य: एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य (अर्थात् आयातों की गणना नहीं की जाती है) का माप दिए गए वर्ष के मूल्य स्तर पर किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ : सरकारी स्वामित्व वाली फैक्टरियाँ।

नौकरीहीन वृद्धि : एक शब्द जिसे 1980 के दशक की स्थिति जब औद्योगिक उत्पादन में उच्च दर पर वृद्धि हुई किंतु औद्योगिक रोज़गार वस्तुतः स्थिर था के संदर्भ के लिए गढ़ा गया।

आर्थिक सुधार : उन नीतियों का अनुसरण जिसका लक्ष्य आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का नियंत्रण और विनियमन समाप्त करना तथा मुक्त बाज़ार को बड़ी भूमिका निभाने की अनुमति देना।

30.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

आई.जे. अहलूवालिया, (1992). *प्रोडक्टिविटी एण्ड ग्रोथ इन इंडियन मैन्यूफैक्चरिंग*, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

फैलोन, पीटर और रॉबर्ट ई.बी. लूकस, (1993). "जॉब सिक्यूरिटी रेग्यूलेशन एण्ड दि डायनामिक डिमांड फॉर इण्डस्ट्रियल लेबर इन इंडिया एण्ड जिम्बाब्वे", *जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स*, खण्ड 40, सं. 2।

लिटिल, इयान एम.डी., दीपक मजूमदार और जॉन एम पेज, जूनियर 1987, स्मॉल मैन्यूफैक्चरिंग एण्टरप्राइसेस: ए कॉम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडिया एण्ड अदर इकोनॉमीज़, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।

नागराज, आर., (2001). "पर्फोमेन्स ऑफ इण्डियाज मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर इन दि 1990 : सम टेण्टेटिव फाइन्डिंग्स", शुजी उचीकावा (संपा.), *इकनॉमिक रिफार्म्स एण्ड इण्डस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन इंडिया*, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकनॉमिक्स, टोक्यो में।

रामास्वामी, के.वी., (1994). "स्मॉल-स्केल मैन्यूफैक्चरिंग इण्डस्ट्रीज : सम आस्पेक्ट्स ऑफ साइज़, ग्रोथ एण्ड स्ट्रक्चर", *इकनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी*, 26।

राय, तीर्थंकर, (2001). "ए स्टडी ऑफ जॉब लॉस विद स्पेशल रेफरेन्स टू डिक्लाइनिंग इण्डस्ट्रीज इन 1990-1998", *लेबर मार्केट एण्ड लेबर इन्स्टीट्यूशन्स*, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनौमीज़ टोक्यो में।

आगामी सांख्यिकीय प्रकाशन

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

इंडियन लेबर ईयर बुक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार।

30.11 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) उद्योगों के दो प्रकार के होने के कारण असंगठित क्षेत्र से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतएव, हमारा मूल्यांकन आंशिक हो जाता है।
2) लघु बनाम बृहत्, आधुनिक बनाम परम्परागत, निजी बनाम सार्वजनिक इत्यादि।
3) एक कारख़ाने द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति 'कर्मचारी' है, जबकि 'कर्मकार' एक कर्मचारी है जो विनिर्माण प्रयिा में काम करता है।
4) भाग 30.2 देखिए।
5) भाग 30.2 देखिए।
6) (क) नहीं (ख) नहीं (ग) हाँ (घ) नहीं

बोध प्रश्न 2

1) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और श्रम मंत्रालय

2) (क) हाँ, (ख) नहीं, (ग) नहीं।

बोध प्रश्न 3

1) 1960-80: सामान्य वृद्धि, 1980-90 प्राय: नगण्य वृद्धि , 1990-97: पुन: वृद्धि शुरू

2) तालिका 3 देखिए।

3) 1980 के दशक में, उच्च वृद्धि दर के साथ-साथ स्थिर रोज़गार। इसलिए, इसे यह कहा जाता है।

4) (क) नहीं (ख) हाँ (ग) हाँ (घ) नहीं

बोध प्रश्न 4

1) तालिका 4 देखिए।

2) 1989 से ह्रास आकृति 1 देखिए।

3) उनका योगदान महत्त्वपूर्ण है; तालिका 6 देखिए।

4) (क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं (घ) हाँ (ड.) हाँ

बोध प्रश्न 5

1) भाग 30.6 देखिए।

2) भाग 30.6 देखिए।

3) (क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं।

बोध प्रश्न 6

1) 1, 2 और 3 के लिए भाग 30.7 देखिए।

2) (क) नहीं (ख) नहीं (ग) हाँ।